MR. CHAIRMAN : No, Please no. Now, next question, Question No. 383. Shri Prakanta Warisa.

SHRI N.K.P. SALVE : Sir, I beg of you to consider one thing. I am asking whether this kind of a study has been conducted in any other State.

MR. CHAIRMAN : But this is not relevant.

SHRI N.K.P. SALVE : Sir, does it go outside the scope and ambit of this question, if I ask whether this kind of a study is also contemplated in any other State ? I beg of you to consider this.

MR. CHAIRMAN : But this is relevant to the earlier question.

SHRI N.K.P. SALVE : If you rule it out, I will sit down, I beg of you to ...

MR. CHAIRMAN : If you had asked this at that time, certainly, I would have allowed you, You are a very senior Member.

SHRI N.K.P. SALVE : I don't want to argue. If you think it is not within the ambit of this question...

MR. CHAIRMAN : Yes, it is not within the ambit of this question.

SHRI N.K.P. SALVE : Thank you, Sir.

*383. The Questioner (Shri Prakanta Warisa) was absent. For answer *vide* page 25 *.infra.*

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री में कमी

*384. **श्री राज मोहिन्दर सिंह** : †

श्री कपिल सिब्बल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमतें बढ़ा दिए जाने के बाद से इसकी बिक्री में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा औसत दैनिक बिक्री कितनी है और यह दूध की कीमत बढ़ाने से पूर्व होने वाली बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत कम है; और

(ग) क्या सरकार ने दूध की बिक्री पुन: बढ़ाने के लिए कोई नये उपाय किए हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) तक एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह द्वारा पूछा गया ।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के बिक्री मूल्य में वृद्धि होने के बाद से इसकी औसत दैनिक बिक्री लगभग 4.00 लाख लीटर से घटकर 2.36 लाख लीटर हो गई है। यह कमी 41 प्रतिशत है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) ग्राही और डिपो एजेंटों को कमीशन में वृद्धि की गई है।

(2) प्रतिदिन 100 लीटर से अधिक दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं के किसी भी समूह के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

(3) होम डिलीवरी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(4) सुबह तथा शाम दोनों, पालियों में डिपो खोलने तथा बंद करने का समय बढ़ा दिया गया है।

(5) थोक आपूर्ति का नया वितरण चैनल शुरू करना।

(6) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

(7) क्षेत्रीय फील्ड अधिकारियों को नए ग्राही अथवा डिपो एजेंट नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

Decline in the sale of DMS Milk

†384. SHRI RAJMOHINDER SINGH†† : **SHRI KAPIL SIBAL :**

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the sale of D.M.S. milk has sharply declined following the enhancement of its price in the recent months;

(b) if so, what is the present average daily sale and the percentage of reduction in sale in comparison to pre-price hike sale; and

(c) whether Government have taken any measures to enhance the sale of milk again; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SUNDAR LAL PATWA) : (a) to (c) A statement is placed on the table of the House.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh.

STATEMENT

(a) and (b) After the increase in sale price of DMS milk, the average daily sale has declined from around 4.00 lakh litres to 2.36 lakh litres. The reduction is 41%.

(c) the following measures have been taken to enhance the sale of DMS milk :—

(1) Commission to the concessionaires & depot agents has been increased;

(2) Incentive has been introduced to any group of consumers purchasing more than 100 litres of milk per day;

(3) Procedure for issue of home delivery cards has been simplified;

(4) Depot opening and closing times both for morning and evening shifts have been extended;

(5) New distribution channel of bulk supply has been started;

(6) Area for supply of DMS milk has been expanded;

(7) Area field officers have been empowered to appoint new concessionaires or depot agents.

श्री राज मोहिन्दर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने दिल्ली मिल्क स्कीम के तहत जो कमीशन की बात कही है वह कमीशन किस शक्ल में होगा और उसकी रकम क्या होगी, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा ? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि सौ लीटर मिल्क जो कंज्यूमर लोग उसको जो आप इंसेटिव देंगे वह किस शक्ल में होगा और कैसे दिया जाएगा ? तीसरा, जब दूध की कीमत 7 रुपए थी तब दिल्ली मिल्क स्कीम उस पर सब्सिडी देता था लेकिन अब जब उसकी कीमत 14 रुपए हो गई, क्या तब भी आप इसमें सब्सिडी देंगे और अगर देंगे तो वह कितनी होगी ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, यह प्रश्न एक बार इसी सदन में उठ चुका है। कंसेसनेयर्स और डिपो एजेंट का कमीशन इन्क्रीज किया गया है। कंज्यूमर्स के लिए होम डिलीवरी काड्र्स का भी प्रावधान किया जा रहा है, डिपो खोलने और बंद करने का समय परिवर्तित किया जा रहा है, इसका समय बढ़ाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के नए चैनल बल्क सप्लाई के लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं, एरिया और बल्क सप्लाई को एक्सपेंड किया जा रहा है। ये सब उपाय अपनाने की कोशिश की जा रही है। परन्तु जो मूल समस्या है, दूध के खपत की, उस पर इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और उसका मैं उत्तर भी दे चुका हूं। मैं यहां पर फिर से दोहराना चाहूंगा कि दूध की वास्तविक खपत जो है वह कम हुई है और कुछ मात्रा में

उसका असर भी पड़ा होगा ऐसा मेरा अनुमान है। इसका मुकाबला करने का हम प्रयास करेंगे और जो सही उपभोक्ता हैं उन तक इसको पहुंचाएंगे।

श्री राज मोहिन्दर सिंह : मिनिस्टर साहब ने सही उत्तर नहीं दिया। मैंने यह भी पूछा था कि जो कंज्यूमर सौ लीटर मिल्क लेंगे क्या उनको आप इंसेंटिव देंगे तो इन्होंने अपने जवाब में कहा कि कंसेशन देंगे। महोदय, दूध की कीमत जब 7 रुपए थी तब गवर्नमेंट, दिल्ली मिल्क स्कीम उस पर सब्सिडी दिया करती थी लेकिन अब जब कि दूध की कीमत 14 रुपए हो गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर भी कोई सब्सिडी दी जाती है ? अगर दी जाती है तो वह कितनी है ? सर, पहले दिल्ली मिल्क स्कीम 4 लाख लीटर दूध बेचता था जो अब घटकर 2.36 लाख लीटर हो गया है लेकिन उसका खर्चा उतना ही है। तो एडवर्टिजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम पर जो खर्चा होता है क्या सरकार उसको घटाने की सोच रही है यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : दूध की जो खपत कम हुई है उसमें दो प्रकार की कमी आई है। एक तो जो दूध का दुरुपयोग होता था, सस्ती कीमत के कारण, वह अब कम हुआ है। दूसरा, कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हो सकते हैं, उनका अलग से सर्वे करना संभव नहीं है, परन्तु कुछ ऐसे उपभोक्ता हो सकते हैं जिन्होंने कीमत बढ़ने के कारण अपनी दूध की खपत कम की हो या उन्होंने दूध लेना बंद किया हो, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु दिल्ली दुग्ध उत्पादन योजना का कुल भाग जो चार लाख लीटर था और इसके कारण से जो यह स्थिति आई है उसको देखते हुए जो इसमें कमी आई है उसको दूर करने के लिए हम सही उपभोक्ताओं तक दूध पहुंचाने का उपाय करेंगे और इसके लिए बल्क में उत्पादन करेंगे, डिपो बढ़ायेंगे, डिपो का समय बढ़ायेंगे, इन सारे उपायों को अपनाया जा रहा है जहां तक कमीशन का प्रश्न है, 500 लीटर तक 40 पैसे पर लीटर और 500 लीटर से अधिक पर 70 पैसे प्रति लीटर होम डिलीवरी पर 50 पैसे प्रति लीटर, 100 लीटर से अधिक पर उपरोक्त कमीशन देने का सोचा गया है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आपके दो सवाल हो गये हैं।

SHRI KAPIL SIBAL : Mr. Chairman, Sir, it is indeed a very alarming situation because the reduction is to the extent of 41 per cent from a total production of four lakhs to 3.3 lakhs. I assume some of it must be on account of malpractices, with milk being sent to the worng quarters. But I think to prevent the malpractice you cannot have a solution which makes it unable for the ordinary consumer to, in fact, purchase the milk. The solution is to deal with the malpractices, the solution cannot be to raise the price from Rs. 7 to Rs. 14 for toned milk, from Rs. 6 to Rs. 11 for double toned milk. Remember

we are the largest milk producing country in the world, with an annual production of 76 million tonnes but the ordinary man in the city cannot buy milk; the reason you give is, 'it is because of the malpractices'. The question that I asked from the Minister is, when they took the decision did they not know that the ordinary consumer cannot afford to buy milk at this price for their children?

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता की दाद देता हूं। ..... **(व्यवधान)** सवाल का जवाब यह है..... **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : जवाब की नहीं, दूध की जरूरत है। ..... **(व्यवधान)**

श्री सुन्दर लाल पटवा : उनके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। श्रीमन मैंने पहले बताया कि दिल्ली में कुल मिला कर 32 लाख लीटर दूध की उपलब्धि हो रही है। उसमें से दिल्ली मिल्क स्कीम का भाग केवल 4 लाख लीटर है अर्थात् एक बटा आठ है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। पार्लियामेंट हाऊस के दोनों डिपोज़ पर जो दूध की खपत होती थी, कीमत बढ़ने के बाद जो खपत हुई है, उससे अंदाज़ा होना चाहिए था कि मिसयूज़ किस प्रकार का और कहां कहां हो सकता है। ..... **(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : तो पार्लियामेंट हाऊस के मिसयूज़ से आप दिल्ली का अंदाजा लगा सकते हैं ? .....**(व्यवधान)**..... He gives an example of misuse in Parliament. It is very strange.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : बड़ा अजीब सवाल है। ..... **(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : कौन से मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट मिसयूज़ करते हैं ? .....**(व्यवधान)**

श्री सुंदर लाल पटवा : मैंने ऐसा नहीं कहा।

SHRI KAPIL SIBAL : Sir, I am sorry. It is a very serious issue. But, yes; there has been certain malpractice.....

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं बहुत गम्भीरता से बात करना चाहता हूं। जहां तक उत्पादकों का सवाल है, उनसे खरीद मूल्य में कोई अंतर नहीं है, उन्हें मदर डेयरी और दूसरे जो खरीद मूल्य देते हैं, वही मूल्य उनको दिया जा रहा है। यह जो कनसेशनल रेट है, यह उपभोक्ताओं के लिए है जो दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा वहन किया जाता था। दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने आप को ट्रांस्फर करने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा। वह कहते हैं कि आप कीमत बराबर करिये तभी हम इसको ग्रहण करेंगे। यह चर्चा चल रही है। दिल्ली शहर में 28 लाख लीटर दूध 14 रुपये प्रति

लीटर बिके और 4 लाख लीटर दूध 7 रुपये लीटर बिके, यह बेसिक बात है। 7 रुपये लीटर अगर झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, ऐसे व्यक्तियों को यह उपलब्ध होता हो तब तो एक बात समझ में आती है। जो आपकी चिंता का विषय है, वही मेरी चिंता का विपय है। यह हमारे लिए गर्व का विपय है कि हमारा देश दुग्ध के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है और उसी मात्रा में दूध भी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। हमारी और आपकी समान चिंता है। परन्तु 7 रुपये लीटर और 14 रुपये लीटर में जो अंतर है, उसमें मेलप्रक्टिसेज को कैसे रोका जाए ? आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति और कोई सुझाव दें कि यह उपाय हो सकता है, मैं उसको हल करने के लिए तैयार हूं। ..... **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपने जो 7 रुपये से 14 रुपये किया है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं .....**(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : यह जो सुझाव आपने दिया है कमीशन बढ़ा देंगे। और डिपोज बढ़ा देंगे, इससे साल्व नहीं होने वाला है। जो गरीब आदमी है जो 7 रुपये में ही खरीद सकता है वह 14 रुपये में नहीं खरीद पाएगा। या तो आप कहिए कि सारा का सारा मिसयूज था—यह जो कीमत का अंतर था 7 रुपये और 14 रुपये का, या तो आप यह कहिए। आप खुद मानते हैं, मंत्री जी खुद मानते हैं कि सारा का सारा मिसयूज नहीं था.....**(व्यवधान)**

श्री सुंदर लाल पटवा : मेरा आपसे फिर आग्रह है.....**(व्यवधान)** मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप दिल्ली सरकार को निवेदन कीजिए, आग्रह कीजिए, आदेश दीजिए कि वह हमसे ले ले और वह 7 रुपये में गरीबों को बेचे।

श्री कपिल सिब्बल : यह अच्छा साल्यूशन है।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मंत्री जी ने कुछ बड़ी बुनियादी बातें कहीं और मुझे समझ में नहीं आया जब मंत्री जी ने कहा कि दूध का दुरुपयोग हो रहा है। दूध का दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ ? अगर मंत्री जी इस पर कुछ स्पष्टीकरण करते तो संभवत: यह उचित रहता। सबसे अधिक दूध का उत्पादन विश्व में भारत कर रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि सामान्य उपभोक्ता तक दुग्ध उपलब्ध हो और ऐसे मूल्यों पर हो जिससे कि वह उसका उपयोग कर सके। यह तो कोई बात नहीं हुई कि दूध का उपयोग.....**(व्यवधान)** आखिर भारत में दूध की उत्पादन लागत जो है क्या वह ऐसी नहीं है कि इसमें सामान्य व्यक्ति दूध को खरीद सके ? क्या मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि इस देश में निर्धन व्यक्ति के लिए दूध आज असंभव बन जाए ? अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री जी यह बताएं कि सामान्य कीमतों पर, ऐसी कीमतों पर दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में दूध कैसे उपलब्ध हो जो उसको पाना चाहते हैं ? समस्या यह है। जो समस्या उत्पन्न हो गई है वह यह हो गई है कि मूल्य बढ़ गए हैं इसलिए उन झुग्गी-झोंपड़ियों तक दुग्ध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.....**(व्यवधान)** मंत्री जी ज़रूर योजना बनाएंगे।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि सारे देश में कहीं भी केन्द्र सरकार दूध की उपलब्धि का प्रबंध नहीं करती है। दिल्ली में यह व्यवस्था पहले से चल रही थी और वह भी 1/8 मात्रा के लिए। अब दिल्ली में केन्द्र सरकार 7 रुपये लीटर दूध बेचे या उसको जारी रखे ·····(**व्यवधान**) सारे देश में कहीं नहीं है—इसलिए दिल्ली में इस व्यवस्था को जारी रखने का औचित्य नहीं था। तो हमने दिल्ली प्रदेश सरकार को आग्रह किया। उन्होंने हमें बताया। जहां तक दुरुपयोग, सदुपयोग का सवाल है—दूध का तो दुरुपयोग नहीं होता है, दूध तो कहीं भी जाता है तो पिया जाता है·····(**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र मोहन : सदुपयोग ही होता है मान्यवर।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सदुपयोग ही होता है। परन्तु यह जो माध्यम है, 4 बजे से अंगोछा बिछाकर लाइन में लगकर 7 रुपये लीटर का दूध लिया जाए और किसी ठेकेदार को 10 रुपये लीटर में दे दें तथा वह ठेकेदार 14 रुपये लीटर में बेचे—यह कैसे रोका जा सकता है, इसका उपाय संभव नहीं है, किसी भी प्रकार संभव नहीं है ऐसा विचार किया गया और इसलिए दिल्ली दुग्ध योजना से आग्रह किया गया कि जिस प्रकार से सारे देश में दुग्ध का, उसकी उपलब्धि के कार्यक्रम का प्रबंध राज्य सरकारें करती हैं निजी संस्थाएं करती हैं उसी प्रकार से दिल्ली का यह 4 लाख लीटर का भी इंतजाम संभाल लें·····(**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र मोहन : मंत्री जी, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है·····(**व्यवधान**)

श्री सभापति : मंत्री जी को बोलने तो दीजिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं आ रहा हूं। अगर 7 रुपये लीटर केन्द्र सरकार दिल्ली में दूध बेचे तो 7 रुपये लीटर मुम्बई में क्यों नहीं बेचे, 7 रुपये लीटर भोपाल और हैदराबाद में क्यों नहीं बेचे ? वहां ग़रीब नहीं हैं ? वहां के गरीब 14 रुपये में पी सकते हैं या 12 रुपये में पी सकते हैं·····(**व्यवधान**) जिसमें भी उनको उपलब्ध होगा। दिल्ली में जो भी कमी हुई है दूध की बिक्री में वह केवल गरीबों का दूध छीना गया है इस कारण कमी नहीं हुई है। इस बात को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। दूध लोगों को मिले, इसकी चिंता आपको, हमको, सबको समान रूप से है।

श्री नरेन्द्र मोहन : मंत्री जी, मेरा प्रश्न यह था कि दूध की जो उत्पादन लागत है वह इतनी अधिक क्यों है ? यह तो बता दें·····(**व्यवधान**) मंत्री जी यह मेरा प्रश्न था।

श्री सभापति : नरेन्द्र मोहन जी, आप बैठिए·····(**व्यवधान**) नो।

SHRI S. R. BOMMAI : Sir, repeatedly the hon. Minister is admitting that our country is the highest milk producing country in the world. Still, the poor people are not in a position to produce it. It is not available to them so far

as Delhi is concerned. What prevents the Central Government in creating a corporation or a body like Anand of Gujarat and hand over the management of distribution?

SHRI SUNDER LAL PATWA : Yes, we are ready. Please ask the Delhi Government to take over this.

केन्द्र सरकार न दूध के उत्पादन का प्रबंध करती है न वितरण का प्रबंध करती है। यह जो कारपोरेशन 'आनन्द' है 'मदर डेयरी' है, ये सारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। जहां तक गरीबों को दूध उपलब्ध कराने का प्रश्न है उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है इसमें समान रूप से सारे देश के बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्रीमती सरला महेश्वरी : केन्द्र सरकार सब्सिडी देने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकारें कहां से देंगी ?

श्री मोहम्मद आज़म खान : मैं बड़े अफसोस और अदब के साथ कहूंगा कि मंत्री जी ने कई बार केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के आपस के झगड़े का जिक्र किया, कहा कि आप तैयार कर लीजिए। ऐसा सदस्यों से कहा.....(**व्यवधान**) बहरहाल जो भी हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में दूध के मामले में या दूसरे मामलों को लेकर तालमेल नहीं है। गरीब आदमी, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले आदमी के लिए आप बहुत परेशान भी हैं। आपने इतनी देर में अपने कई स्टेटमेंट्स बदले भी हैं। आपने यह भी फरमाया कि उसके सदुपयोग दुरुपयोग के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। सदुपयोग ही होता है। पहले आपने यह भी बताया कि हमारी खपत कम हो गयी है। जब दूध की खपत कम हो गयी है तो जाहिर है सरकारी डिपो से बिकने वाले दूध की जब खपत कम होगी तो उसका उपयोग ही नहीं होगा। सदुपयोग और दुरुपयोग की बात तो यहां तय हो जाएगी कि वह दूध कहां जाता है। हम इस सच्चाई को बड़ी ईमानदारी से कहते हैं। जब हम सदस्यों को दूध लेना होता है तो अपने पड़ोस में जब 7 रुपये का यहां बिकता था तब 10 रुपये का मिलता था और अब जब 14 रुपये का हुआ है तो मात्र 15 रुपये में मिलता है। यह बिल्कुल सच्चाई है। यहां के, लोक सभा और राज्य सभा के दोनों स्टेशंस से दूध कहां जाता है ? सदस्य ले जाते हैं या दूसरे लोग—यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है, सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्यों के दूध ले जाने से गरीब आदमी को दूध नहीं मिलता है, झुग्गी झोंपड़ी तक दूध नहीं पहुंचता है तो सदस्यों का दूध बंद करने के बाद क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि झुग्गी में दूध देने की व्यवस्था केन्द्र सरकार अपनी तरफ से करने की कोई योजना रखती है ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : श्रीमन् बार-बार दोहराकर वही सवाल फिर से दोहराया जा रहा है। जब दिल्ली में सरकार नहीं थी तब केन्द्र ने जिम्मेदारी समझ कर यह प्रबंध अपने हाथ में

लिया था कि यहां दूध की उपलब्धि की व्यवस्था की जाए। परन्तु अब दिल्ली में सरकार है। सारे देश में कहीं भी केन्द्र सरकार दूध की उपलब्धि का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेती है। अगर गरीबों की चिंता करनी है.....**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : राजधानी दिल्ली में ही है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : जहां तक दूध के सदुपयोग-दुरुपयोग का प्रश्न है..... **(व्यवधान)** दूध के सदुपयोग-दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है, दूध के नाम पर जो कीमत का फर्क है उसका नाजायज लाभ उठाने का सवाल है वह मैंने निवेदन किया।

श्री मोहम्मद आज़म खान : यह सरकार वही तो देखेगी।

PROF. M. SANKARALINGAM : Hon. Sir, the Minister has accepted that sale proceeds have declined to 40% due to increase of milk price from Rs. 7 to 14. He is prepared to help the poor but the responsibility is with the Delhi Government. Why can't the Delhi Government, the Central Government and concerned Minister have a talk among themselves to evolve a new scheme to distribute milk at a lower rate? Now, he has increased the price of milk to ease the situation to that extent it has further increased the thirst of the poor people for milk. I would like to know from the hon. Minister whether he would invite the State Governments for evolving a theory by which milk is available at the rate of Rs. 10 per kg. and is distributed in a judicious manner.

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, दिल्ली सरकार से जब बात-चीत चली तब उन्होंने इसी बात पर आग्रह किया कि आप कीमत बढ़ा करके, बराबरी पर ला करके हमें सौंपना चाहते हैं तब हम विचार करेंगे और कीमत बराबरी पर लाने के बाद में उससे विचार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इस व्यवस्था को लेने पर राजी हो जाएगी।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर सवाल है, अभी आपने सिब्बल साहब के प्रश्न के उत्तर में और श्री नरेन्द्र मोहन जी के प्रश्न के उत्तर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही और आपने अपने उत्तर में यह फर्माया कि आप जैसे सदस्य कुछ अच्छे सुझाव दें तो उन पर विचार करके फिर कुछ निर्णय करेंगे। .....**(व्यवधान)** हां, बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों के सुझावों पर। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कृषि मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या जब तक इनके सुझाव आपको प्राप्त हो करके कोई समाधान नहीं हो जाए तब तक आप बढ़ी हुई कीमतें रोक करके उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, आज की जो वस्तुस्थिति है वह जारी रहेगी और इस संबंध में आपके सुझाव आयेंगे तो मैं आपके सुझाव दिल्ली सरकार को भेज दूंगा।